हो, चाहे सड़कें हों चाहे अस्पताल हों और चाहे इर्रीगेशन का मामला हो, क्या मंत्री जी इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि यह कान्करेन्ट लिस्ट में है, स्टेट गवर्नमेन्ट को आदेश देंगे एग्जम्पशन के लिए और यह कहेंगे कि वह इस काम को शुरू कर दे और जो स्कीमें और प्रोग्राम हरिजनों और ट्राइब्ल्स के लिए बने हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को इजाजत देगी।

SHRI YOGENDRA MAKWANA : We cannot give such a blanket permission to the State Governments. We have prescribed a precedure for laying of transmission lines and drinking water supply scheme. This procedure has been simplified and a shorter procedure has been suggested to the State Governments. We sanction as early as possible, but such a blanket permission cannot be provided to any State Government, because already the State Governments, particularly UP and MP, have violated the Act.

Villages connected by All Weather Roads

*411. SHRIMATI MADHURI SINGH† :

SHRI GHULAM MOHD. KHAN: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to lay a statement showing :

(a) the total number of villages connected by all weather roads till date and the outlays provided to the States in the current year, State-wise;

(b) whether it is a fact that there are wide disparities among various States in regard to development of various roads; and

(c) the steps proposed to achieve better results in development of roads in the rural areas ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a)A Statement is attached.

(b) Yes, Sir.

(c) The construction of rural roads is taken up by the State Governments mainly under the Minimum Needs Programme which is in the State sector.

In order to enable the State Governments to take up more rural roads construction works, this Ministry has advised the States to take up these works under the newly introduced Rural Landless Employment Guaranttee Programme. The State Governments have also been permitted to take up rural road works under the National Rural Employment Programme.

Statement

(Rs. in crores)

Sl. No.	State/UT	No. of villages connected by all weather roads as on 31.3.1983	Outlay approved for rural roads under MNP during 1983-84
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	10682	11.50
2.	Assam	11789	7.50
3.	Bihar	20996	30.00

1	2	3	4
4.	Gujarat	10577	5.00
5.	Haryana	6583	0.05
6.	Himachal Pradesh	6755	6.50
7.	Jammu & Kashmir	3571	4.00
8.	Karnataka	7857	10.00
9.	Kerala	1268	4.00
10.	Madhya Pradesh	15148	12.00
11.	Maharashtra	11730	18.50
12.	Manipur	412	2.25
13.	Meghalaya	2305	1.00
14.	Nagaland	628*	0.50
15.	Orissa	1242	5.50
16.	Punjab	12018	—
17.	Rajasthan	5737	7.60
18.	Sikkim	210	3.00
19.	Tamil Nadu	12246	11.34
20.	Tripura	1745	3.10
21.	Uttar Pradesh	10056	58.00
22.	West Bengal	17250	8.50
23.	Andaman & Nicobar Islands	15	0.80
24.	Arunachal Pradesh	207	2.00
25.	Chandigarh	22	—
26.	Dadra & Nagar Haveli	52	—
27.	Delhi	236	0.02
28.	Goa, Daman & Diu	403	0.05
29.	Lakshadweep	@	—
30.	Mizoram	100	2.75
31.	Pondicherry	298	0.28
	Total :	172138	215.66

*Figure as on 31.3.1982.

@There are no villages. There are islands.

श्रीमती माधुरी सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 31-3-83 तक 20,996 गांवों को सभी मौसम में काम आने वाली सड़कों से जोड़ दिया गया है परन्तु यह नहीं बताया गया है कि कुल कितने ऐसे गांव बिहार राज्य में हैं, जिन्हें जोड़ना है तथा अभी तक कुल गांवों का कितना प्रतिशत ऐसी सड़कों से जोड़ा गया है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर दिया है, उसके लिए पहले प्रश्न को देखा जाए कि उसमें क्या कहा गया है :

> "the total number of villages connected by all weather roads till date and the outlays provided to the States in the current years, State-wise ;

ये आंकड़े थे, जो मैंने दे दिए हैं। अब कितने प्रतिशत इस तरह की रोड्स हैं, जो आल वेदर रोड्स बनाई गई हैं, वह मैं नहीं बता सकता। इतना मैं कह सकता हूं कि मैंने जो सूचना यहां पर दी, वह भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों से जो सूचना संकलित की गई है, उसके आधार पर दी है। मिनीमम नीड्स प्रोग्राम, जिसका हमने हवाला दिया है, उसके लिए दरअसल प्लानिंग कमीशन जब प्लान आऊटलेज भिन्न-भिन्न सरकारों के लिए निश्चित करता है उसी में रोड्स के लिए कुछ रकम इयर मार्क कर देता है। उन्हीं के आधार पर मैंने उत्तर दिया है। दरअसल, मेरा मंत्रालय तो एक पोस्ट आफिस की तरह काम कर रहा है। मुझे जो सूचना मिली है, उसी के आधार पर मैंने जवाब दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि नीडल मिनिस्ट्री हम लोगों की है।

श्रीमती माधुरी सिंह : छठी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1164 करोड़ रुपए का प्रावधान है और इस मंत्रालय का सीधा उत्तरदायित्व है लेकिन ग्रामीण सड़क विकास कार्य में बड़ी विषमता है। बिहार के गांवों में सड़कों की बड़ी कमी है परन्तु 1983-84 के लिए केवल 30 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है जो बहुत कम है। क्या सरकार अब गांवों के लिए सड़कें बनाने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाना चाहती है।

श्री हरिनाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिया है, उससे मैं प्लानिंग कमीशन को और राज्य सरकार को अवगत करा दूंगा। प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि मेरे मंत्रालय से भी नेशनल रूरल लेंडलेस इमप्लाइमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत सड़कों की मंजूरी दी जाती है। बिहार के संबंध में मैं अभी नहीं बता सकता लेकिन जो 600 करोड़ रुपया उपलब्ध था उसमें से 400 करोड़ से ज्यादा वितरित किया जा चुका है भिन्न-भिन्न राज्यों को। इस 400 करोड़ में से 217.68 करोड़ रुपया इस तरह की सड़कों के निर्माण के लिए दिया है। जहां तक एन. आर. ई. पी. प्रोग्राम है, उसमें मैं पक्की सड़क के संबंध में नहीं कह सकता, लेकिन 367627 किलोमीटर सड़क बनाई गई है, कच्ची या पक्की, यह मैं अभी नहीं कह सकता।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल भारत के गांवों की सड़कों से संबंधित है। सड़क एक ऐसा साधन है जिसके बगैर विकास नहीं हो सकता। गांधी जी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है। मंत्री महोदय का यह जवाब कि यह मेरा मंत्रालय नहीं है, यह उचित नहीं है। सभी मंत्रालयों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। दूसरे मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करना मंत्री महोदय का कर्तव्य है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि बुनियादी सवाल है कि कुल कितने गांव सड़क के बिना हैं और कब तक सरकार उन गांवों में सड़क देगी। क्या सरकार की यह मंशा है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय मैं इसके सम्बन्ध में केवल यही सूचना देना चाहता हूं –

All villages with a population of 1,500 and above and 50 per cent of the villages with a population of 1,000 to 1,500 are to be linked by all weather roads by 1980. A cluster of villages project has to be adopted in cases of hilly, tribal, desert and coastal areas where villages with population of less than 1,000 can also be taken up.

During the Sixth Five Year Plan, 50 per cent of the above physical programme is to be achieved.

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। यह नीतियों का सवाल है। ऐसे गांव हैं जहां दल दल है और बारिश में वे बिल्कुल कट जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नीति तो यही है कि सारी सड़कें बनाई जाएंगी।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरी बात का जवाब नहीं आया है। मंत्री महोदय स्वयं भी बिहार के रहने वाले हैं।

SHRI A.R. MALLU : Are there any instances, which have come to the notice of the Government of India, where the States have ignored the guidelines of the Government of India in implementing the roads programme, especially from Andhra Pradesh and, if so, what action is proposed to be taken to implement the guidelines of the Central Government in every State ?

MR. SPEAKER : The question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Financial Assistance to Karnataka Government for provision of Drinking Water

*405. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state ;

(a) the financial assistance sought by Government of Karnataka during the drought in the year 1982-83 for providing drinking water in affected villages and problem villages in that State ;

(b) the extent to which the financial assistance was given and the number of problem villages which have been covered for making drinking water available during the recent drought ;

(c) whether Central Government have authorised any agency to check the grant and proper use of Central asssistanc ; and

(d) whether the allocated amount has been fully utilised and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : (a) and (b) The Ministry of Agriculture which is concerned with the subject of drought relief has indicated the assistance that against the demand of the Govt. of Karnataka for relief-assistance to the extent of Rs. 23.56 crores for drinking water supply in the drought affected areas, the following ceiling of expenditure was sactioned during 1982-83 and 1983-84 :-

	Crores
(i) Tubewell programmes in rural areas for sinking of 6500 tubewells :	Rs. 11.05
(ii) Urban water supply	Rs. 1.54
(iii) Drinking water transportation :	Rs. 0.50
	Rs. 13 09 crores.